



Neutral Citation No-2026:AHC:2061

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं - 2916 वर्ष 2025

शिव पूजन पांडेय याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: रमाकांत तिवारी

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अचल सिंह, : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं - 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. ग्राम गढ़वाड़ा, परगना और तहसील कर्वी, जिला चित्रकूट के संबंध में 6.12.2013 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम (इसके बाद यू.पी.सी.एच. अधिनियम कहा जाता है) की धारा 4(2) के तहत अधिसूचना को रद्द करने के लिए प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है।
2. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिकांश ग्रामीण चकबंदी अभियान के पक्ष में नहीं हैं और वे अपनी जोत और गांव में उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट हैं; इसलिए, यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 4(2) के तहत अधिसूचना को यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 6(1) के तहत अधिसूचना की घोषणा द्वारा रद्द किया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में चकबंदी निदेशक के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है; हालांकि, इस पर अभी भी विचार लंबित है।
3. स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान चकबंदी निदेशक द्वारा अधिक उचित रूप से किया जा सकता है; इसलिए याचिकाकर्ता को चकबंदी निदेशक के समक्ष एक नया प्रतिनिधित्व पेश करने की अनुमति दी जा सकती है। आगे यह तर्क दिया गया है कि यदि न्यायालय द्वारा निर्देशित निर्धारित अवधि के भीतर याचिकाकर्ता द्वारा



पेश किए जाने वाले अभ्यावेदन के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपरोक्त के रूप में इस सम्मेलन में, प्रस्तुत याचिका को लंबित रखने में कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा; इसलिए, रिट याचिका को मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना अंतिम रूप से निपटाया जाता है, जिसमें प्रस्तुत याचिकाकर्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आज से तीन सप्ताह के भीतर दिन के आदेश की प्रमाणित प्रति और रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ लखनऊ में चकबंदी निदेशक के समक्ष एक नया अभ्यावेदन पेश करे। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद, चकबंदी निदेशक संबंधित प्राधिकारी से कानून के अनुसार, शीघ्रता से, अधिमानतः पांच महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट मांगने के बाद इसका निर्णय लेगा।

5. उपरोक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 5, 2026

पी.पी.

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)